Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 22-08-2006
Participants : Patil Shri Shivraj V.,Jha Shri Raghunath,Yadav Shri Devendra Prasad,Patil Shri Shivraj V.

an>

Title : Shri Raghunath Jha called the attention of Minister of Home Affairs to the situation arising out of the absence of Border Roads resulting in the increase in ISI and Naxalite activities on Indo-Nepal Border and steps taken by the Government in this regard.

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय मैं गृह मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विाय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

> "भारत-नेपाल सीमा पर सीमा सड़क के न होने, जिसके फलस्वरूप आईएसआई और नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम "

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): India-Nepal border is an open border having a length of 1751 kilometres covering five States, viz., Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim. Nationals of both the countries are free to cross over to the other side under the Indo-Nepal Treaty of Friendship, 1950.

The Government of India is seized of the matter of development of infrastructure along India-Nepal border, including development of road network in border areas so as to facilitate patrolling by the Shashtra Seema Bal (SSB) which has been deployed as the Border Guarding Force on the India-Nepal Border as also to promote further development of the border areas. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Silence please. Important matter is being discussed. The hon. Minister is making a statement.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Please note this. SSB has already identified 657 kilometres of roads in the border districts of Bihar which are of operational significance to them and which should be constructed/upgraded in the areas along India-Nepal border. Discussions are under way with respective State Governments and it is expected that the list of roads to be taken up for construction/upgradation

---

*Placed in Library, See No. LT 4829/06.

will be finalized soon. The suggestions by the hon. Members for roads in border districts of Betia, Motihari, Sitamarhi, Madhubani, Supaul, Araria and Purnea as well as the specific road—Adapur-

Raxaul-Ghorasahan-Shivhar-Sitamarhi-Darbhanga-Saharsa-Kishanganj will be considered keeping in view the operational requirements of SSB.

The Government of India is also actively considering establishment of four Integrated Check Posts (ICPs) at Raxaul and Jogbani in Bihar and Sonauli and Nepalganj Road in Uttar Pradesh on India-Nepal border. These check posts will house regulatory agencies namely, Immigration, Customs, border security together with support facilities like parking, warehousing, banking, hotels etc., in a single complex equipped with all modern amenities. Road connectivity to these ICPs will also be improved simultaneously.

Sir, 18 Battalions of the SSB have been deployed along the India-Nepal border to keep a strict vigil over the movement of undesirable elements. The Government has already sanctioned 20 additional battalions of SSB to have proper control over the border. SSB has already established 266 BOPs all along the Indo-Nepal border and appropriate directions have been given to the field units to exercise effective vigilance to prevent infiltration by undesirable elements. Intensive Patrolling and "Nakas" continue to be carried out.

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके महत्व को समझते हुए इस बात को स्वीकारा है कि शीघ्र ही राज्य सरकार से वार्ता करके बिहार की 600 किलोमीटर से ऊपर की इंडो-नेपाल बॉर्डर की सड़क को मजबूत और अपग्रेड करके बनाया जाएगा। मैंने अपने ध्यानार्काण प्रस्ताव में कुछ बातों का जिक्र किया था लेकिन उन सब का माननीय गृह मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

महोदय, ट्रीटी के मुताबिक हमारे इलाके में आम आदमी को इधर से उधर जाने की स्वतंत्रता है लेकिन बड़े पैमाने में हथियारबंद माओवादी बिहार के बॉर्डर में घुसते हैं, क्राइम करते हैं, थाना लूटते हैं, पुलिस के हथियार लूटते हैं, दर्जनों से ऊपर राइफल्स लूटे गए हैं और लोगों की हत्याएं की हैं ।

हमारे माननीय सदस्य श्री सीताराम सिंह जी सदन में बैठे हैं, बिहार में इनके घर पर हमला हुआ। सैकड़ों की संख्या में औरतों-मर्दों पर हमला किया, कुछ गिरफ्तारियां हुईं तथा कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोग मारे गए। उनमें से अधिकांश लोग नेपाल के माओवादी हैं। चूंकि ध्यानार्काण में बताया है कि बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए आपने एस.एस.बी. को लगाया है। लेकिन हमारे यहां नेपाल से निकलने वाली कोसी, गंडक, बागमती, कमला तथा अदवारा समूह की जो नदियां हैं, इन नदियों के कारण लगभग पांच-छः महीने तक एस.एस.बी. का जो मूवमैन्ट होना चाहिए, वह मूवमैन्ट अच्छी सड़कें न होने के कारण नहीं हो पाता है और वहां व्यापक रुप से तस्करी होती है। नकली करेन्सी, नकली नोट लाते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की एजेन्सी आई.एस.आई. के जरिये पांच सौ रुपये के नकली नोटों के साथ अधिकतर लोग बिहार में प्रवेश करते हैं। वहां इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। आधुनिकतम हथियारों में ए.के.-47, ए.के.-56 जैसे हथियार दूसरी जगह मिलने मुश्किल हैं, लेकिन नेपाल के बाजार से चाहे हमारे यहां के क्रिमिनल्स हों, वहां के क्रिमिनल्स हों या नक्सली लोग हों, उनके कारण पूरा उत्तर बिहार, पश्चिमी चम्पाणरण और पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा से लेकर किशनगंज तक तथा पूर्णिया, सहरसा और सुपौल ये सारे क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं। इनको रोकने के लिए आपने नदी के किनारे जवान तो बढ़ाये हैं। लेकिन सुरक्षा बल दौरे कर सकें, पूरी विजिल रख सकें और सीमाओं की सुरक्षा कर सकें, इसके लिए आपने कोई प्रबंध नहीं किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में भी विचार करें।

1317 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अब भारत सरकार को गफलत में नहीं रहना चाहिए तथा हमें अपनी स्थिति को समझना चाहिए। पहले हमने तिब्बत को बफर स्टेट समझा था और हम अपनी सीमा का चौकसी नहीं कर पाये। हमें तब जितना मुस्तैद होना चाहिए था, हम उतने मुस्तैद नहीं रह पाये। आज का नेपाल वह नेपाल नहीं है, जिसके साथ 1950 में संधि हुई थी। आज नेपाल में ल्हासा तथा चीन से 24 से 48 घंटे में हमारी सीमा पर बड़े से बड़े हथियार आ सकते हैं। बड़े से बड़े लड़ाई के साज-सामान तथा गाड़ियां आ सकती हैं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए आपको इन सारी चीजों पर विचार

करना चाहिए। आपने नेपाल की सड़क को स्वीकार किया है, लेकिन आप इसे जल्द से जल्द बनवाने, चालू करने और इन इलाकों में विशेा नियंत्रण करने की कार्रवाई करने का कट करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस विाय की गंभीरता को समझा है। लेकिन इसे कुछ और अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। यह विाय भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क निर्माण का विाय है। यह विाय न केवल राट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच मैत्री बनाये रखने से संबंधित है तथा भारत-नेपाल की सीमा में हो रही माओवादी गतिविधियों के कारण वहां के अमन-चैन और शांति से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह विाय अत्यंत संवेदनशील है। यह राट्रीय और अंतरराट्रीय महत्व का विाय है। चूंकि सामरिक दृटिकोण से नेपाल हमारा मित्र देश है। हमारी और नेपाल की मित्रता है। लेकिन भारत-नेपाल के बार्डर के इलाकों में आये दिन जो घटनाएं घटती हैं, जिनके विाय में माननीय सदस्य रघुनाथ झा ने बताया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार का जो वक्तव्य आया है, उसमें दो बातें और स्पट करने की आवश्यकता है। एक बात यह आई है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर गश्त को सुकर बनाने के लिए एस.एस.बी. ने बिहार की सीमा से लगे सीमावर्ती जिलों में 657 किलोमीटर लम्बी सड़कों की पहले ही पहचान कर ली है।उनके लिए आपरेशनल दृटि से महत्वपूर्ण है। एक उन्होंने यह जवाब दिया है और यह पॉजीटिव है। लेकिन इसके बाद जो जवाब आया है, भारत नेपाल सीमा के साथ लगे क्षेत्र जिनका निर्माण किया जाना है, उसके बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ अभी विचार-विमर्श चल रहा है। यह विचार-विमर्श किस अवधि तक चलेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित होगी ? यह जो विचार-विमर्श की प्रक्रिया है, यह विचार-विमर्श क्या किसी समय-सीमा के अंदर होगा ?

आशा की जाती है और उसमें जवाब यह है कि निर्माण उन्नयन के लिए शुरू की जाने वाली सड़कों की सूची को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा जब ध्यानार्काण प्रस्ताव में जो विाय उठाया गया है, यह जो सीमा वर्ती क्षेत्र जो मोतीहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और किशनगंज हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह ऑपरेशनल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। दोनों तरफ ऑपरेशनल मामला है। एक तरफ यह है कि ऑपरेशनल दृटि से यह 657 कि.मी. महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ फिर कहा गया है कि जो विशेा सड़क है, उस पर भी एसएसपी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा यह कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार नहीं करिए, बल्कि जब यह स्पट रूप से रेखांकित है कि जो नेपाल-भारत सीमावर्ती इलाका है, वहां राट्रीय सड़क का निर्माण करना है, इन सड़कों के निर्माण की दिशा में सरकार क्या कोई सकारात्मक पहल करेगी और कब से यह निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ? जो विचार-विमर्श की प्रक्रिया है, तो विचार-विमर्श तो सिर्फ एक ही राज्य सरकार, उत्तर बिहार से करना है तथा और जो पांच राज्यों से यह मसला जुड़ा हुआ है और उनसे विचार-विमर्श करना है, मैं खासकर यह जानना चाहता हूं कि आज जो सबसे ज्यादा घटना घट रही है, उत्तर बिहार से जो नेपाल की सीमा सटी हुई है, 19 जिलों में सबसे ज्यादा माओवादी गतिविधियां और राट्रविरोधी गतिविधियां चल रही हैं तथा स्मगलिंग भी हो रही है और अपराध करने वाले लोगों को नेपाल के रास्तों से आधुनिक अस्त्र-शस्त्र मिल जाता है। हालांकि नेपाल से हमारी दोस्ती है और नेपाल की जनता और भारत की जनता शांति और चैन चाहती है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आपका प्वाइंट आ गया है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसीलिए वहां शांति और अमन कायम रखने के लिए आपके सुरक्षा बल को मूवमेंट में करने के लिए इस सीमा सड़क को कब से प्रारम्भ किया जाएगा ? इस सीमा-सड़क के निर्माण की दिशा में सरकार क्या सकारात्मक कदम उठा रही है, मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विाय पर बोलना चाहता हूं। मुझे भी इस पर बोलने का समय दिया जाए।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा भी कॉलिंग अटैंशन का मामला है, मैंने सुबह ही नोटिस दिया है। कृपया करके मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :मेरी एक बात सुन लीजिए। पहले आप बैठ जाइए। पहली बात यह है कि नियमों के अनुसार जिन माननीय सदस्यों के नाम आए हैं, उनको ही बोलने का समय दिया जा सकता है। दो मैम्बर्स के नाम थे, उनको मैंने बोलने का समय दे दिया। मैं आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज मेरे पास बहुत बिजनैस है, उस बिजनैस को खत्म भी करना है, इसलिए अन्य माननीय सदस्यों को इस विाय पर बोलने के लिए समय नहीं दिया जा सकता।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मैंने एक माननीय सदस्य को समय दिया तो सभी को समय देना पड़ेगा। योगी जी, अगर मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा तो मुझे सभी को समय देना पड़ेगा। इसलिए आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : योगी जी, आप बैठ जायें, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Home Minister to reply on the Calling Attention.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister to reply on the Calling Attention. He is on his legs.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Home Minister is on his legs. Please sit down.

... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अलाऊ नहीं कर सकता Shri Aditya Nath, I feel very sorry for you, but please sit down.

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नोटिस नहीं आया है। Please sit down.

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आप लिस्ट में से देख सकते हैं, इसमें आपका नाम नहीं है। अगर मैं एक को भी अलाऊ करूंगा तो सब को अलाऊ करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कर सकता।

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Aditya Nath, it is not possible for me to accommodate you at this point of time. Therefore, please sit down. Nothing is going on record.

*(Interruptions)**

---

*Not Recorded.
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI E.V.K.S. ELANGOVAN): Sir, how can you allow him to go on like this?

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record. Please sit down.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Aditya Nath, you should understand my problem also. If I give you time to speak, then I will have to give time to all the hon. Members, and I would have to accommodate them all. Therefore, please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: According to rules, only those hon. Members who have given their names in writing can be accommodated to speak. Therefore, please sit down.

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : योगी जी, आप बैठ जायें। अगर मैं आपको टाइम दूंगा तो सब को टाइम देना पड़ेगा।

*(Interruptions)**

उपाध्यक्ष महोदय :योगी जी, आप बैठ जायें। आप मेरी यह बात समझ लें।

श्री शिवराज वि. पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा पूछा गया कि नक्सलवादी लोग, जो उधर से आ रहे हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :योगी, जी, आप बैठ जायें, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है ।

*(Interruptions)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। मैं क्या करूं?

*(Interruptions) **

---

*Not Recorded.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, how can two Members speak at the same time? Let the Minister be allowed to give his reply. If the hon. Member wants to raise any queries, he can do so at the end. He is constantly interrupting the Minister. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर कुछ भी नही जा रहा है।

*(Interruptions)**

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, यहां पूछा गया कि नक्सलवादी लोग अगर नेपाल से इधर आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। यह सही बात है और अच्छा सवाल है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर हमारी जो एस.एस.बी की फोर्सेज़ हैं, उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। आज यदि 20 बटालियन वहां पर हैं तो और 20 बटालियन खड़ी करके हम वहां पर सीमा की रक्षा करने का काम हम करने जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्क्म में कुछ सड़कें कच्ची सड़कें हैं। उनको पक्का बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। ये जो सड़कें बनने जा रही हैं, यह काम यदि नेशनल हाईवेज़ का होता तो पूरी तरह से केन्द्र सरकार की तरफ से किया जाता। मगर राज्य में जो सड़कें हैं, उसमें राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाता है, उनको भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से सड़कें बनानी चाहिए। ये पक्की सड़कें बनाने का काम हमने हाथ में लिया है। यहां पर हमने बताया कि कुल सड़कों की लंबाई 1751 किलोमीटर की है। इसमें से 1558 किलोमीटर की सड़कें हम बनाने जा रहे हैं।

जहां तक बिहार का सवाल है, उसकी सीमा 726 किलोमीटर की है और वहां पर हम जो सड़कें बनाने जा रहे हैं, करीब-करीब 607 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं। ये जो सड़कें बनने जा रही हैं, उसमें प्रांत की सरकारों को भी पूछना है और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। उनको हमने बताया है कि जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए कि किस प्रकार से यहां पर सड़कें बननी हैं ताकि उनकी कोई राय और इच्छा हो तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया जा सके। हमने सभी राज्यों की सरकारों को लिखा है।

---

*Not Recorded.

उत्तरांचल की सरकार को लिखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा है और उसी प्रकार से बिहार तथा सिक्किम की सरकार को भी लिखा है। उनकी तरफ से जो जानकारी हमारे पास आएगी, उसको लेकर अंतिम निर्णय करने के समय उसको ध्यान में रखेंते

हुए निर्णय किया जाएगा और उसके मुताबिक यह काम किया जाएगा।

चौथी चीज़ जो हम इस संबंध में करने जा रहे हैं, वह यह है कि इन बॉर्डर्स पर हम जो नई बटालियन्स रेज़ कर रहे हैं, उनके हैडक्वार्टर्स हम वहां पर बनाने जा रहे हैं। हमने खासकर बिहार सरकार को कहा है कि इस बॉर्डर में ही आप हमें जगह दीजिए जहां पर हमारी नई बटालियन्स हमें रेज़ करनी हैं, वह वहां पर रखी जाएं। उसमें एस.एस.बी. की बटालियन होंगी, सी.आर.पी. की बटालियन भी होंगी और खासकर सरहद के इलाकों में इन् बटालियन्स को खड़ा करने का काम भी किया जा रहा है। उसके बाद राज्य सरकारों को बताया है कि आप भी अपनी इंटैलिजैन्स एजेन्सी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। गांवों में इंटैलिजैन्स कम है। तालुका और जिला में इंटैलिजैन्स लेने के लिए आई.बी. या रॉ उतनी काम में नहीं आती मगर स्टेट की इंटैलिजैन्स मशीनरी को मालूमात लेना जरूरी है।

पहले यह काम अच्छा होता था, लेकिन आजकल यह देखा जा रहा है कि उतना अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए सारी प्रांतों की सरकारों को हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से इंटेलीजेंस मशीनरी को बढ़ाइए और फिर कीजिए। उन्होंने यह भी कहा है कि आपका जो डेप्लॉयमेंट फोर्स है, आप कुछ कम्पनियां सिर्फ एक्शन करने के लिए रखिए, उन्हें आप लॉ-ऐंड-आर्डर मेन्टेन करने के लिए, ट्रैफिक मेन्टेन करने के लिए मत रखिए, मगर उन कम्पनियों को आप इसी काम के लिए रखिए। इस प्रकार से यह काम किया जा रहा है

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह उत्तर देना चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार इसमें पैसे से मदद करेगी और प्रांत की सरकार भी करेगी। ये काम कहीं-कहीं बार्डर रोड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन से होगा और कहीं-कहीं स्टेट गवर्नमेंट के सीपीडब्ल्यूडी से भी हम करवाना चाहते हैं और दूसरे जो पब्लिक सैक्टर अंडरटैकिंग्स हैं, उनसे भी करवाना चाहते हैं। इसलिए यह रोड भी बनेगी और यह जो नकसलिज़्म को कंट्रोल करने का मसला है, उस पर भी हम इस प्रकार से नियंत्रण पा सकेंगे।